

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 112
गुरुवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

श्रमिकों का पुनः कौशल विकास (री-स्किलिंग)

112. डा. फौजिया खान:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तकनीकी उद्योग में एआई को अपनाने और वैश्विक मांग में बदलाव के कारण वर्ष 2025 में 50,000 से ज्यादा छंटनी का, विशेषकर उन शुरुआती और मध्यस्तरीय की नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;
- (ख) मंत्रालय की शहरी और युवा वर्गों में नौकरी के नुकसान और बेरोजगारी में बढ़ोतरी को कम करने के लिए पुनः कौशल विकास (री-स्किलिंग) और संक्रमण कार्यक्रमों को समर्थन करने की क्या योजनाएँ हैं;
- (ग) सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और विस्थापित तकनीकी श्रमिकों को समाहित करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या मंत्रालय कार्यबल कौशलों को भावी प्रौद्योगिकीय मांगों के साथ संरेखित करने के लिए उद्योग और शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय कर रहा है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): नैसकॉम की अगस्त 2024 में प्रकाशित "एडवांसिंग इंडियाज एआई स्किल्स" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई प्रतिभा के वर्ष 2027 तक 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 6 लाख-6.5 लाख पेशेवरों से 12.50 लाख पेशेवरों से अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होने की संभावना है। अब तक, एआई/बिग डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों के 3.20 लाख अभ्यर्थियों सहित 8.65 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन/प्रशिक्षण लिया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "राष्ट्रीय एआई पोर्टल" (<https://indiaai.gov.in/>) लॉन्च किया है, जो एआई से संबंधित पहलों, अकादमिक अनुसंधान, स्टार्टअप, नीति विकास और विचार नेतृत्व लेखों के व्यापक भंडार के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल नैतिक एआई, तकनीकी प्रगति और उद्योग जगत की प्रवृत्तियाँ जैसे विषयों को कवर करने वाले वेबिनार और ऑनलाइन सत्र भी आयोजित करता है

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 18.56 लाख से अधिक अभ्यर्थी फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पर जुड़े हैं, जिनमें से 3.37 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है।

सरकार युवाओं को उद्योग जगत संबंधी कौशल से लैस करने और उन्हें उभरते तथा नए जमाने की नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के साथ अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग को कार्यान्वित कर रही है।

इसके अलावा, एमईआईटीवाई द्वारा नासकॉम की साझेदारी से कार्यान्वित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत, स्टार्टअप्स को विनिर्माण कंपनियों के उपयोग हेतु एआई आधारित टूल और एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है। कंपनियों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में ऐसे कई उपाय प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), एमईआईटीवाई ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए 'युवाआई: एआई के साथ युवाओं की उन्नति और विकास' नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को समावेशी तरीके से एआई तकनीक और सामाजिक कौशल प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को 8 विषयक क्षेत्रों- कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटी तथा विधि और न्याय में एआई कौशल सीखने और प्रयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

एआईसीटीई ने तकनीकी और उच्च शिक्षा को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने तथा छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख उपायों में अनिवार्य इंटरनशिप के साथ परिणाम-आधारित मॉडल पाठ्यक्रम की शुरुआत और दिशानिर्देशों के माध्यम से उद्योग-अकादमिक गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है जो उद्योग जगत के पेशेवरों के साथ सहयोग और जुड़ाव की सुविधा प्रदान करते हैं। संस्थानों को उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और एआईसीटीई ने शैक्षणिक कार्यक्रमों में उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए सेल्सफोर्स, एडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, सीडीएसी, बजाज फिनसर्व, व्हीबॉक्स जैसे और अन्य प्रमुख संगठनों के साथ सहयोग किया है।
